Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 19, Issue No. 6, December-2022, ISSN 2230-7540

वत्तीय समावेशन और व्यापक वकास में सहकारी स मतियों का प्रभाव

Rakesh Meena[1]*, Vikram Meena[2]

[1] Research Scholar, University of Rajasthan

[2] Research Scholar, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur

सार - समावेशी वत्तीय प्रणाली को बढ़ावा देना कई देशों में नीतिगत प्राथ मकता मानी जाती है। गरीब कसानों, ग्रामीण गैर-कृ ष उद्यमों और अन्य कमजोर समूहों की जीवन स्थितियों में सुधार के लए वत्तीय समावेशन महत्वपूर्ण है। जब क वत्तीय समावेशन के महत्व को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है, भारतीय अर्थव्यवस्था में छोटे उधारकर्ताओं के लए ऋण प्रवाह के आधार पर वत्तीय समावेशन की सीमा के आकलन का अभाव है। उदारीकृत, तेजी से वैश्विक, बाजार संचा लत भारत की अर्थव्यवस्था आज समावेशी वकास को सु वधाजनक बनाने में वफल रही है। यह पेपर वत्तीय समावेशन की सीमा का मूल्यांकन करके इस अंतर को भरने का प्रयास करता है और भारत में वत्तीय समावेशन के महत्वपूर्ण उपकरणों के रूप में सहकारी स मतियों की स क्रय भागीदारी पर जोर देता है।

कीवर्ड- वत्तीय समावेशन, भारतीय अर्थव्यवस्था, समावेशी वकास, सहकारी बैंक, एएफसी

----------X----------

1 परिचय

भारत में वत्तीय समावेशन की अध्यक्षता वाली स मति ने वत्तीय समावेशन को परिभा षत कया है, "वत्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्र क्रया और कमजोर वर्गों जैसे कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूहों को सस्ती कीमत पर समय पर और पर्याप्त क्रे डट की आवश्यकता होती है"। वत्तीय समावेशन एक महत्वपूर्ण कड़ी है और समावेशी वकास हा सल करने की दिशा में पर्याप्त पहला कदम है। वत्तीय समावेशन में बैंक खातों जैसे वत्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच शा मल होनी चाहिए - खाते में चेक, तत्काल क्रे डट, बचत उत्पाद, प्रेषण और भुगतान सेवाएं, बीमा - स्वास्थ्य देखभाल, बंधक, वत्तीय सलाहकार सेवाएं और उद्यमी क्रे डट। भारत सरकार का वत्तीय समावेशन का वस्तार करने के लए काम करने का एक लंबा इतिहास रहा है। 1969 में प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक बड़ा कदम था। 1975 में GOI ने इसी उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की। इसने वशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं के शाखा वस्तार को प्रोत्साहित कया। बैंकों को आरबीआई के दिशानिर्देश से पता चलता है क उनके शुद्ध बैंक ऋण का 40% प्राथ मकता क्षेत्र को उधार दिया जाना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से कृ ष, लघु उद्योग, खुदरा व्यापार आदि शा मल हैं। हमारी 80% से अ धक जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृ ष पर निर्भर है। इस लए शुद्ध बैंक ऋण का 18% कृ ष ऋण में जाना चाहिए। केवाईसी मानदंडों का हा लया सरलीकरण एक और मील का पत्थर है। [1]

फर भी बैंक वत्तीय समावेशन के सपने को पूरा करने के लए संघर्ष कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है क बैंकों द्वारा तैयार कए गए उत्पाद निम्न आय वाले परिवारों को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। 100 देशों के बीच बैं कंग सेवाओं की पहुंच की सीमा का पता लगाने के लए वत्तीय समावेशन के पहले सूचकांक में, भारत को 50वां स्थान दिया गया है। केवल 34% भारतीय व्यक्तियों के पास बैं कंग सेवाओं तक पहुंच है या वे प्राप्त करते हैं। वत्तीय रूप से बहिष्कृत भारतीय व्यक्तियों की सूची में मुख्य रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वं चत वर्ग जैसे कसान, छोटे वक्रेता, कृ ष और औद्यो गक मजदूर, असंगठित क्षेत्रों में लगे लोग, बेरोजगार व्यक्ति, महिलाएं, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक और शारीरिक रूप से अक्षम लोग

www.ignited.in

शा मल हैं। वत्तीय बहिष्कार का मुख्य कारण निय मत या पर्याप्त आय की कमी है। ज्यादातर मामलों में कम आय वाले लोग ऋण के लए योग्य नहीं होते हैं। वत्तीय सेवा की निकटता एक और तथ्य है। नुकसान न केवल परिवहन लागत है बल्कि कम आय वाले व्यक्ति के लए दैनिक मजदूरी का नुकसान भी है। बहिष्कृत अ धकांश उपभोक्ताओं को बैंक के उन उत्पादों के बारे में जानकारी नहीं होती है, जो उनके लए फायदेमंद होते हैं। स्थानीय साहूकार से अपनी वत्तीय आवश्यकताओं के लए धन प्राप्त करना बैंक से ऋण प्राप्त करने की तुलना में आसान है। अ धकांश बैंकों को अपने ऋण के लए संपार्श्विक की आवश्यकता होती है। कम आय वाले व्यक्ति के लए बैंक ऋण के लए संपार्श्विक प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। इसके अलावा, बैंक अपने वत्तीय लक्ष्यों को पूरा करने को अ धक महत्व देते हैं। इस लए वे बड़े खातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। छोटे ऋण देना और लाभ कमाना बैंकों के लए लाभदायक नहीं है। [2]

2. भारत में वत्तीय समावेशन

2.1 वत्तीय समावेशन - उठाए गए कदम

वत्तीय समावेशन पर आयोग की रिपोर्ट 2012 तक बहिष्कृत भारतीय ग्रामीण परिवारों के कम से कम 50 प्रतिशत (50.77 म लयन) और शेष 2015 तक वत्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लक्ष्य के साथ एक राष्ट्रीय ग्रामीण वत्तीय समावेशन योजना की स्थापना की सफारिश करती है। इस संख्या को बढ़ाने के लए भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने अ भनव कदम उठाए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के योगदान से बचत बैंक खातों में ओवरड्राफ्ट सु वधा, उदारीकृत शाखा वस्तार, एटीएम के लए उदारीकृत नीति, प्रौद्यो गकी उत्पादों और सेवाओं का परिचय, प्री-पेड कार्ड, मोबाइल बैं कंग, साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों / सहकारी स मतियों को अनुमति देने जैसी बैं कंग सेवाओं में वकास हुआ है। बीमा और वत्तीय उत्पाद बेचने के लए ऑपरेटिव बैंक, वत्तीय साक्षरता कार्यक्रम, वशेष नि ध का निर्माण आदि। [3]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की नई शाखाएं खोलने के कारणों में से एक यह सुनिश्चित करना है क बैं कंग सेवा गरीबों के लए सुलभ हो। अन्य कदमों में बहिष्कृत क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करना, शहरी सूक्ष्म वत्त और सूक्ष्म वत्त संस्थानों की अलग श्रेणी के उपाय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बैंक रहित क्षेत्रों में बैं कंग सेवाओं का वस्तार करना और प्राथ मक कृ ष ऋण स मतियों (PACS) और अन्य सहकारी स मतियों का उपयोग करना शा मल है। बहिष्कृत समूहों के वत्तपोषण के लए समूह दृष्टिकोण अपनाने के लए बैं कंग चैनल और सहकारी स मतियों के रूप में। [4]

ले कन व भन्न अनुमान स्रोतों और सर्वेक्षणों से यह स्पष्ट है क अभी भी 50% ऋण व्यावसायिक जरूरतों के बजाय आपात स्थिति को पूरा करने के लए हैं। यहां तक क अमीर लोगों को भी बाहर रखा गया है, यहां तक क अमीर लोगों को भी ऋण उद्देश्यों के लए गैर-संस्थागत स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रौद्यो गकी की अनुपस्थिति, पहुंच और कवरेज की अनुपस्थिति, डलीवरी तंत्र की अनुपस्थिति, व्यवसाय मॉडल न होने आदि के कारण भी वत्तीय बहिष्करण बना रहता है। वर्तमान परिदृश्य में वत्तीय समावेशन की प्र क्रया में सहकारी बैंकों की स क्रय भागीदारी अपरिहार्य हो जाती है क्यों क वश्व स्तर पर, देश सहकारी स मतियों के पैठ लाभ को भुनाने के माध्यम से ही समावेशी वकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। [5]

2.2 दुनिया भर में सहकारी स मतियों का दायरा

संयुक्त राज्य में, 10 में से 4 व्यक्ति एक सहकारी बैंक (40%) के सदस्य हैं। यूरोप में सहकारी बैंकों में 150 म लयन से अ धक ग्राहक (यूरोपीय संघ की आबादी का एक तिहाई), 60,000 बैं कंग डेस्क, 50 म लयन सदस्य हैं। फ्रांस में, 21,000 सहकारी स मतियाँ 700,000 लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। जर्मनी में, 8,106 सहकारी स मतियाँ 440,000 लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। यूरोप में सहकारी बैंक मांस उत्पादों के 74%, डेयरी उत्पादों के 96%, अंडे के उत्पादन के 50%, वानिकी उत्पादों के 34% और बैंकों में कुल जमा रा श के 34.2% के लए जिम्मेदार हैं। कोरिया में कृ ष सहकारी स मतियों में 2 म लयन से अ धक कसानों (सभी कसानों का 90%) की सदस्यता है, जो 11 बि लयन अमेरिकी डॉलर का उत्पादन है। कोरियाई मत्स्य सहकारी स मतियां भी 71% की बाजार हिस्सेदारी की रिपोर्ट करती हैं। भारत में, 239 म लयन से अ धक लोग एक सहकारी स मति के सदस्य हैं। जापान में, कृ ष सहकारी स मतियों की सदस्यता में सभी जापानी कसानों का 91% हिस्सा है। चीन में 180 म लयन सदस्य हैं। मले शया में 5.4 म लयन सदस्य हैं जो जनसंख्या का 20% है। जापान के सभी जापानी परिवारों में लगभग 5 में से 1 एक स्थानीय रिटेल को-ऑप से संबं धत है और सभी को-ऑप सदस्यों में से 90% महिलाएं हैं। संगापुर में, उपभोक्ता सहकारी स मतियों के पास सुपरमार्केट खरीद में 55% बाजार है और 700 म लयन अमरीकी डालर का

www.ignited.in

कारोबार है। संगापुर में, 50% जनसंख्या (1.6 म लयन लोग) एक सहकारी स मति के सदस्य हैं। [6]

2.3 सहकारिता रोजगार सृजित करती है

सहकारी स मतियाँ दुनिया भर में 100 म लयन से अ धक रोजगार प्रदान करती हैं, बहुराष्ट्रीय उद्यमों की तुलना में 20% अ धक। कनाडा में, सहकारी स मतियों और क्रे डट यूनियनों में 160,000 से अ धक लोग कार्यरत हैं। कोलम्बिया में, सहकारी आंदोलन 109,000 नौकरियां प्रदान करता है जो स्वास्थ्य क्षेत्र में 23% रोजगार, परिवहन क्षेत्र में 18% रोजगार, श्र मक औद्यो गक क्षेत्र में 13%, वत्तीय क्षेत्र में 11% और 9% है। कृ ष क्षेत्र में।

2.4ण् भारत की जनसांख्यिकीय रूपरेखा

भारत की जनसांख्यिकी समग्र रूप से उल्लेखनीय रूप से व वध है। लगभग 1.13 बि लयन से अ धक लोगों की भारत की जनसंख्या में वश्व की जनसंख्या का लगभग छठा हिस्सा शा मल है। भारत मूल रूप से एक कृ ष प्रधान अर्थव्यवस्था है, जिसकी कुल जनसंख्या का 72% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। भारत के पास बहुत बड़ा अवसर है क्यों क यह भौगो लक रूप से व वध है और हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा अ वक सत है इस लए इसमें काफी गुंजाइश है। भारत की प्रमुख समस्या जनसंख्या से संबं धत है। उद्योग के मामले में, सी मत क्षमता अ धक रोजगार की मांग को पूरा नहीं कर सकती है। [7]

2.5 भारत में सहकारी स मतियों का वकास

राष्ट्रीय सहकारी वकास निगम (NCDC) की स्थापना 1963 में NCDC अ धनियम 1962 के तहत कृ ष उपज के उत्पादन, वपणन और निर्यात को बढ़ावा देने के लए की गई थी। आज, सहकारी स मतियाँ भारत के प्रत्येक गाँव को कवर करती हैं। सहकारी स मतियों का कृ ष ऋण वतरण का 46%, उर्वरक वतरण का 36%, चीनी उत्पादन का 59%, गेहूं की खरीद का 32% और भंडारण सु वधा का 65% हिस्सा है। उर्वरक उत्पादन और वतरण में भारतीय कसान उर्वरक सहकारी (इफको) का 35 प्रतिशत से अ धक बाजार पर कब्जा है, जिसमें 50 म लयन से अ धक कसान जुड़े हुए हैं। चीनी के उत्पादन में बाजार की सहकारी हिस्सेदारी 58 प्रतिशत से अ धक है और कपास के वपणन और वतरण में उनकी हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत है। हस्त-बुनाई क्षेत्र में 55 प्रतिशत करघे सहकारी क्षेत्र का है। सहकारी स मतियां 50 प्रतिशत खाद्य तेलों का प्रसंस्करण, वपणन और वतरण करती हैं। राष्ट्रीय डेयरी वकास बोर्ड के नेतृत्व में और 15 राज्य सहकारी दुग्ध वपणन संघों के माध्यम से संचा लत डेयरी सहकारी स मतियाँ अब दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गई हैं। [8]

2.6 भारतीय सहकारी क्षेत्र के ग्रे क्षेत्र

खराब बुनियादी ढाँचा, जागरूकता की कमी, गुणवत्ता प्रबंधन की कमी, सरकार पर अत्य धक निर्भरता, निष्क्रिय सदस्यता, चुनावों का असंचालन, मजबूत मानव संसाधन नीति का अभाव, व्यावसायिकता की उपेक्षा, प्रतिबं धत कवरेज भारतीय सहकारिता के कुछ उदास क्षेत्र हैं। सहकारिताएं मजबूत संचार और जनसंपर्क रणनीतियों को वक सत करने में भी असमर्थ हैं जो जनता के बीच सहयोग की अवधारणा को बढ़ावा दे सकती हैं।

भारत में गरीबी उन्मूलन के लए वत्तीय समावेशन एक बड़ा कदम है। ले कन इसे प्राप्त करने के लए, सरकार को एक कम परिप्रेक्ष्य वाला वातावरण प्रदान करना चाहिए जिसमें सहकारी बैंक कम आय वाले उपभोक्ताओं तक पहुँचने के लए आवश्यक नवाचारों को आगे बढ़ाने के लए स्वतंत्र हों और फर भी लाभ कमा सकें। ग्रामीण वत्तीय सेवा प्रदाताओं को इन उपभोक्ताओं और उन तक पहुँचने के लए नए व्यापार मॉडल के बारे में अ धक सीखना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में, नवोन्मेषी व्यवसाय मॉडल के अनुकूलन के माध्यम से भारतीय सहकारी बैंक-कृ ष वत्त निगम की सफलता का केस अध्ययन प्रासं गक होगा। इसकी चर्चा अगले भाग में की गई है।

3. साहित्य की समीक्षा

गोल्डबर्ग **(2005)** ने व भन्न अध्ययनों और साहित्य के अवलोकन के साथ पुष्टि की है क सूक्ष्म वत्त कार्यक्रम आय बढ़ा सकते हैं और परिवारों को गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। अन्य परिणामों के बीच तक पहुंच। [9]

एस. डू, बी.सी. भट्टाचार्य और एस. सेन, **(2007)** सीएसआर के लए उपभोक्ता प्रति क्रयाओं पर एक ब्रांड की सामाजिक पहलों को उसकी प्रतिस्पर्धी स्थिति (यानी, एक सीएसआर स्थिति) में एकीकृत करने की सीमा के मॉडरेटिंग प्रभाव की जांच करते हैं। हम पाते हैं क उपभोक्ताओं द्वारा आयोजित सकारात्मक सीएसआर वश्वास न केवल अ धक खरीद संभावना के साथ जुड़ा हुआ है बल्कि दीर्घका लक वफादारी और वकालत के व्यवहार के साथ भी जुड़ा हुआ है। इससे भी महत्वपूर्ण

बात यह है क हम पाते हैं क सभी सीएसआर पहल समान नहीं बनाई गई हैं: एक ब्रांड जो खुद को सीएसआर पर रखता है, अपनी सीएसआर रणनीति को अपनी मुख्य व्यवसाय रणनीति के साथ एकीकृत करता है, उन ब्रांडों की तुलना में अ धक संभावना है जो केवल सीएसआर- व शष्ट श्रेणी का लाभ उठाने के लए सीएसआर में संलग्न हैं। उपभोक्ता डोमेन में लाभ। [10]

चट्टोपाध्याय **(2011)** ने भारतीय राज्यों को तीन श्रे णयों में वर्गीकृत कया है, यानी वत्तीय समावेशन की उच्च, निम्न और मध्यम सीमा वाले राज्य जो तीन बुनियादी आयामों (1) बैं कंग पैठ (2) बैं कंग सेवाओं की उपलब्धता और (3) के उपयोग पर आधारित है। बकाया जमा और ऋण की मात्रा के साथ बैं कंग प्रणाली। [11]

चट्टोपाध्याय **(2011)** ने भारतीय राज्यों को तीन श्रे णयों में वर्गीकृत कया है, यानी वत्तीय समावेशन की उच्च, निम्न और मध्यम सीमा वाले राज्य जो तीन बुनियादी आयामों (1) बैं कंग पैठ (2) बैं कंग सेवाओं की उपलब्धता और (3) के उपयोग पर आधारित है। बकाया जमा और ऋण की मात्रा के साथ बैं कंग प्रणाली। [12]

टी. रॉय और के. सेन **(2015)** जिला सहकारी बैंक पछड़े क्षेत्रों में एसएचजी के लए जमा जुटाने और सूक्ष्म ऋण के सं वतरण में प्रमुख भू मका निभा रहे हैं। वे ऋणों के समय पर पुनर्भुगतान के लए बार-बार क्रे डट भी प्रदान करते हैं। रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इनवेस्टमेंट फंड (सीआईएफ) एनआरएलएम द्वारा एसएचजी को वत्तीय वश्वास और मुख्यधारा के बैंक वत्त को आक षत करने के लए एक स्वस्थ ट्रैक रिकॉर्ड बनाने के लए प्रदान कया जाता है। [13]

एग्वु, एन.पी. **(2016)** ने खुलासा कया क सहकारी बैंकों के माध्यम से वत्तीय सेवाओं तक पहुंच के संबंध में व भन्न आयु समूहों से संबं धत लाभा थयों की धारणाओं के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। [14]

एस. सेनापति और ए. भाटिया**, (2018)** भारत में सोसायटी की संख्या, सदस्यता, जमा, उधारकर्ताओं की संख्या, उन्नत ऋण के संदर्भ में सहकारी ऋण वशेष रूप से प्राथ मक कृ ष ऋण सोसायटी (PACS) के वकास का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। यह पैक्स को पुनर्जी वत करने और पुनर्जी वत करने के लए वैद्यनाथन स मति सहित व भन्न स मतियों द्वारा कए गए उपायों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। अध्ययन के नतीजे बताते हैं क सहकारी बैंकों के माध्यम से वत्तीय समावेशन का गरीबी उन्मूलन पर सीधा और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है क वत्तीय समावेशन के माध्यम से बचत, ऋण, बीमा, ऋण आदि जैसी बुनियादी वत्तीय सेवाओं तक पहुंच ने गरीबों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है और उन्हें गरीबी के चंगुल से बाहर निकालने में मदद की है। [15]

4. भारत में व्यापक वकास

4.1 सहकारी स मतियों के माध्यम से भारत में वत्तीय समावेशन की सफलता के लए पूर्वापेक्षाएँ

भारतीय एएफसी मामले का अध्ययन स्पष्ट रूप से प्रकाश में लाता है क सहकारी स मतियों की भागीदारी के बिना भारत में वत्तीय समावेशन की सफलता लगभग असंभव है। इस सफलता को हकीकत बनने के लए जरूरी है क उपयुक्त तकनीक, उपयुक्त और कुशल वतरण मॉडल, मुख्यधारा के बैंकों का दृढ़ संकल्प और भागीदारी, बैंकों के बीच मजबूत सहयोग, तकनीकी सेवा प्रदाता, बिजनेस चैनल सेवाएं, सभी की भागीदारी, वशेष रूप से जमीनी स्तर पर राज्य प्रशासन। रूट लेवल और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट मॉडल का उदारीकरण

4.2 अपने ग्राहक (केवाईसी) को अपने ग्राहक को बढ़ाने के साधन के रूप में जानें (जीवाईसी)

वर्तमान में अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंड सभी प्रकार के ग्राहक खातों पर लागू होते हैं। यह न केवल ग्राहक की पहचान करता है बल्कि ग्राहक की गति व धयों को भी समझता है, और यह सुनिश्चित करता है क ग्राहक के खाते/खातों में संचालन वास्त वक उद्देश्य के लए है/हैं। केवाईसी मानदंडों का अनुप्रयोग व भन्न कारणों से महत्वपूर्ण हो गया है। नशीली दवाओं की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी गति व धयों, ह थयारों के लेन-देन आदि के कारण कई मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बैंकों को अपने ग्राहकों के साथ व्यवहार करने में सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

 वत्तीय समावेशन मुख्य रूप से उन गरीबों पर केंद्रित है जिनके पास औपचारिक वत्तीय संस्थागत समर्थन नहीं है और उन्हें स्थानीय साहूकारों के चंगुल से छुड़ाना है। इस दिशा में पहले कदम के रूप में, हमारे कुछ बैंक अब सामान्य प्रयोजन के क्रे डट कार्ड और कारीगर क्रे डट कार्ड के साथ आगे आए हैं जो संपार्श्विक-मुक्त लघु ऋण प्रदान

www.ignited.in

करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के साथ, हमारे बैंक अब निम्न आय वर्ग के लए "नो फ्रल" खातों की पेशकश कर रहे हैं। लेन-देन में कुछ प्रतिबंध के साथ इन खातों में या तो कम न्यूनतम या शून्य शेष है। व्यक्तिगत बैंक के पास यह तय करने का अ धकार है क खाते में शून्य या न्यूनतम शेष रा श होनी चाहिए या नहीं। वत्तीय संस्थानों के संयुक्त प्रयास से मार्च 2006-2007 के बीच छह म लयन नए 'नो फ्रल' खाते खोले गए। बैंक अब समग्र वातावरण में वत्तीय समावेशन को व्यवसाय के अवसर के रूप में मान रहे हैं जो वकास को सुगम बनाता है। आरबीआई ने 'नो फ्रल' खाता खोलने के लए केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) मानदंडों को सरल बना दिया है। यह कम आय वाले व्यक्ति को बिना पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण के 'नो फ्रल' खाता खोलने में मदद करेगा।

ऐसे मामलों में बैंक कसी मौजूदा ग्राहक से व्यक्ति का परिचय ले सकते हैं जिसकी पूर्ण केवाईसी मानदंड प्र क्रया पूरी हो चुकी है। और परिचयकर्ता का कम से कम 6 महीने तक बैंक के साथ संतोषजनक लेन-देन होना चाहिए। यह सरलीकृत प्र क्रया उन लोगों के लए उपलब्ध है जो एक साथ सभी खातों में 50,000 रुपये से अ धक की शेष रा श रखने का इरादा रखते हैं। इस सु वधा से हम कम आय वाले समूह से अप्रयुक्त, काफी मात्रा में धन को औपचारिक अर्थव्यवस्था में ले जा सकते हैं। बैंकों को अब गैर-सरकारी संगठनों, एसएचजी और अन्य नागरिक समाज संगठनों की सेवा का उपयोग मध्यस्थ के रूप में व्यापार सु वधाकर्ता और व्यापार संवाददाता मॉडल के उपयोग के माध्यम से वत्तीय और बैं कंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति है।

5. उपसंहार

सहकारी बैंकों को सुर क्षत और जीवंत संस्थाओं में वक सत करने के लए उन्हें कुशल होने की आवश्यकता है। बैं कंग प्रौद्यो गकी शहरी बैं कंग प्रणाली के लए जगह में है। इस लए सहकारी बैंकों को इस तकनीक को एक अवसर में बदलने के बारे में स क्रय होना चाहिए। बाजार की मौजूदा प्रवृ त्त और नीति निर्माताओं का सुझाव है क बैंकों के लए बेहतर अस्तित्व के लए, आकार महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। वत्तीय पुनर्गठन और संस्थागत सुधार का संयोजन केवल सहकारी बैंकों को दक्षता में सुधार करने में मदद कर सकता है। सरल, छोटे, कफायती उत्पादों के प्रावधान से निम्न आय वाले परिवारों को औपचारिक वत्तीय क्षेत्र में लाने में मदद मलेगी। कम आय वाले उपभोक्ताओं तक सीधे पहुंचने की बैंकों की सीमाएं हैं। संवाददाताओं को एक उत्कृष्ट चैनल माना जा सकता है जिसका उपयोग बैंक अपने उत्पाद की जानकारी वतरित करने के लए कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को वत्तीय लाभों और बैंकों के उत्पादों के बारे में श क्षत करना जो कम आय वर्ग के लए फायदेमंद हैं, उनकी क्षमता का दोहन करने के लए एक अच्छा कदम होगा।

दक्षता को आउटपुट के इनपुट के अनुपात से मापा जाता है, जहां इस अनुपात का एक बड़ा मूल्य बेहतर प्रदर्शन का संकेत देता है। एक सहकारी बैंक के प्रदर्शन की संकल्पना उस हद तक की जाती है, जिस सीमा तक बैंक अपने संसाधनों का उपयोग व्यापार लेनदेन उत्पन्न करने में सक्षम है और इसे एक दक्षता अनुपात द्वारा मापा जाता है। बैंकों के प्रदर्शन का वश्लेषण करने के लए तकनीकी दक्षता (टीई) पर वचार कया जाता है। TE वस्तुओं और सेवाओं के दुर्लभ कारक इनपुट और आउटपुट के बीच संबंध को संद र्भत करता है। स्केल दक्षता तकनीकी दक्षता का वह घटक है जिसे ऑपरेशन के आकार के लए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह देखा गया है क वर्तमान वर्षों के दौरान सहकारी बैंकों की शुद्ध तकनीकी दक्षता में गरावट की प्रवृ त्त दिखाई दी है। स्केल ए फ शएंसी के मामले में भी इसी तरह की प्रवृ त्त देखी गई है।

कॉर्पोरेट संस्कृति में बदलाव से स्थायी दक्षता भी आएगी और इस तरह सहकारी स मतियाँ मजबूत निजी खला ड़यों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। सहकारी उद्यमों के प्रबंधन में व्यावसायिकता नवीनतम वकास के साथ कर्मचारियों की गुणवत्ता को उन्नत करेगी और प्रबंधकों और निदेशक मंडल के सदस्यों के बीच एक उ चत और सौहार्दपूर्ण संबंध भी वक सत करेगी। सहकारी नेताओं और पेशेवर अ धकारियों दोनों के लए उ चत और निरंतर प्र शक्षण होना चाहिए। चावल, चीनी, फल, सब्जियां जैसी कई कृ ष वस्तुएं हैं; मसाले आदि जिनका निर्यात बाजारों में मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है। वदेशी बाजार में कृ ष सहकारी स मतियां इसका लाभ उठा सकती हैं। दृष्टि, समर्पण, प्रतिबद्धता और सबसे बढ़कर अ भनव दृष्टिकोण वाला नेतृत्व प्रतिस्पर्धा के युग में सहकारी पहचान को बनाए रखने में मदद कर सकता है।

संदर्भ

1. डॉ. के.सी.चक्रबर्ती, डप्टी गवर्नर, आरबीआई "वत्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना - मुद्दे,

चुनौतियां और आगे की राह", 17 जुलाई, 2009 को मुंबई में 20वें स्कॉच शखर सम्मेलन 2009 में प्रस्तुति।

2. रंगराजन स मति (2008), वत्तीय समावेशन स मति की रिपोर्ट, भारत सरकार।
3. "अफ्रीका में ग्रामीण वत्त चुनौतियों को संबो धत करने में नवाचार" अफ़्राका तकनीकी कार्यशाला, 26 नवंबर 2008 www.afraca.org।
4. डॉ. के. श्रीहर्ष रेड्डी, "आंध्र प्रदेश में छोटे उधारकर्ताओं के बीच वत्तीय समावेशन की सीमा पर एक अध्ययन", प्रबंधन, वज्ञान और प्रौद्यो गकी में अनुसंधान के स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय जर्नल वॉल्यूम - 1 नंबर -1 जनवरी-जून 2011।
5. मोहन राकेश (2006), "आ र्थक वकास, वत्तीय गहनता और वत्तीय समावेशन", वा र्षक बैंकर्स सम्मेलन 2006, हैदराबाद में संबोधन।
6. बसंत कुमार और ब्रजराज मोहंती, "भारत के वशेष संदर्भ के साथ सार्क देशों में वत्तीय समावेशन और समावेशी वकास" वलक्षण, एक्सआईएमबी जर्नल ऑफ मैनेजमेंट वॉल्यूम VIII अंक 2 सतंबर 2011।
7. वश्व बैंक (2006), "द क्षण ए शया में सूक्ष्म वत्त-गरीबों के वत्तीय समावेशन की ओर"।
8. अरोड़ा रश्मि उमेश, (2010), "मेजरिंग फाइनें शयल एक्सेस", ग्र फथ यूनिव र्सटी, ऑस्ट्रे लया, जून।
9. गोल्डबर्ग, एन। (2005)। माइक्रोफाइनेंस के प्रभाव को मापना: हम जो जानते हैं उसका जायजा लेना। ग्रामीण फाउंडेशन यूएसए प्रकाशन श्रृंखला, 1-52।
10. दू, एस., भट्टाचार्य, सी.बी., और सेन, एस. (2007)। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी से संबंधपरक पुरस्कार काटना: प्रतिस्पर्धी स्थिति की भू मका। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन मार्केटिंग, 24(3), 224-241।
11. चट्टोपाध्याय (2011)। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर औपचारिक वत्त का प्रभाव। द जर्नल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, 32(2), 234-262।
12. बोलास-अराया, एचएम, और सेगुई-मास, ई। (2014)। सहकारी बैंकों में स्थिरता रिपोर्टिंग यूरोप में उनके प्रकटीकरण का वश्लेषण।
13. रॉय, टी., और सेन, के. (2015)। एसएचजी-गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक सकारात्मक छलांग। द मैनेजमेंट अकाउंटेंट जर्नल, 50(7), 12-15।
14. एग्वु, पीएन (2016)। नाइजीरिया में कृ ष उत्पादन, आ र्थक वकास और गरीबी उन्मूलन पर कृ ष वत्तपोषण का प्रभाव। जर्नल ऑफ बायोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड हेल्थकेयर, 6(2), 36-42
15. सेनापति, एस., और भाटिया, ए. (2018)। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समावेशी वकास की दिशा में पैक्स के योगदान पर एक अध्ययन। सैद्धांतिक अर्थशास्त्र पत्र, 8(13), 2818।

Corresponding Author

Rakesh Meena*

Research Scholar, University of Rajasthan

www.ignited.in